सीएमओ तिवारी ने 7 साल बढ़ा ली नौकरी

अमानगंज तबादला होने के बाद हुआ खुलासा, रिटायरमेंट के बाद दो साल तक बने रहे सीएमओ

- 2023 की बजाय 2029 में रिटायर होने फर्जीवाड़ा
- दो साल में किए करोड़ों के भुगतान

सुरेश पाण्डेय

पन्ना, 11 जुलाई. पन्ना नगर के मूल निवासी तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों में सीएमओ पद पर पदस्थ रहे दिनेश तिवारी की अधिकांश नौकरी पन्ना एवं छतरपुर में रही. हाल ही उनका छतरपुर जिले की राजनगर परिषद से पन्ना जिले की अमानगंज नगर परिषद में सीएमओ पद पर पदस्थापना की गई थी.

इसी बीच सीएमओ तिवारी का फर्जीवाड़ा उनके आधार कार्ड एवं पेनकार्ड में अंकित जन्मतिथि से उजागर हो गया. जिसके आधार पर उनको 2023 में ही रिटायर हो था. इसके बाद तत्काल नगरीय प्रशासन संचालनालय ने उनसे जन्मतिथि के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार, पेन कार्ड एवं हाई स्कूल की अंकसूची आदि मांगी गई. लेकिन उन्होंने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और न ही उन्होंने नगर परिषद अमानगंज में ज्वाइन किया. जिससे पोर्टल में उपलब्ध पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की जन्म तिथि के आधार पर संचालनालय नगरीय प्रशासन ने तत्काल उन्हें सागर ज्वाइंट डायरेक्टर के यहां अटैच कर दिया और उनकी सेवानिवृत्ति के आदेश भी जारी कर दिये.

ज्ञात हो कि राजनगर नगर परिषद में पदस्थ रहे सीएमओ दिनेश तिवारी का स्थानांतरण बीते 17 जून को पन्ना जिले के अमानगंज नगर परिषद में किया गया था. जिसके बाद उन्हें राजनगर नगर परिषद से रिलीव कर दिया गया. लेकिन अमानगंज नगर परिषद में ज्वाइन करने से पहले ही उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई कर दी गई. उनके ऊपर भ्रामक जानकारी देकर नौकरी करने के आरोप लगे थे. जिसमें जांच के बाद सत्यता पाए जाने पर उन्हें सागर जेडी कार्यालय में अटैच कर दिया गया है और मामले की जांच चल रही है. सीएमओ दिनेश तिवारी के आधार कार्ड और पेन कार्ड में 17 नवम्बर 1961 जन्म तिथि अंकित है. जिसके आधार पर उनका रिटायरमेंट 2023 में होना था.

इनका कहना है...

दस्तावेजों में गड़बड़ी की सूचना मिलने पर वरिष्ठ कार्यालय को पत्र लिखकर मामले की जानकारी देते हुए जांच करने के लिए कहा था. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है. फिलहाल उन्हें राजनगर नगर परिषद् से रिलीव कर दिया गया था.

साजिदा कुरेशी, पीओ डूडा छतरपुर

1980 में छतरपुर जिले में पहली पदस्थापना : दिनेश तिवारी ने सन 1980 के पहले नगर सुधार न्यास छतरपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर ज्वाइन किया था. लेकिन कुछ वर्षों बाद विभाग बंद हो जाने के कारण इनका संविलियन नगरीय निकाय में कर दिया गया. इसके बाद वह छतरपुर, पन्ना, राजनगर सहित अन्य नगरीय निकायों में सीएमओ बने हैं. सीएमओ तिवारी के दस्तावेजों के अनुसार उन्हें वर्ष 2023 में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, इसके बाद भी वह राजनगर और छतरपुर नगरीय निकाय में पदस्थ रहे. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के भुगतान भी कर डाले. अपर आयुक्त ने कार्रवाई कर सीएमओ दिनेश तिवारी को सेवानिवृत्त करते हुए उनके द्वारा सेवानिवृत्ति तिथि के बाद प्राप्त की गई परिलब्धियों की वसूली और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है. वहीं कार्यालयीन अभिलेख के आधार पर सीएमओ दिनेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग में अटैच किया गया. एडवोकेट दिनेश प्रजापति ने बताया कूटरचित दस्तावेज तैयार करने, लोक रजिस्टर में छेड़छाड़ करने और उनका उपयोग करने पर बीएनएस की धाराएं 336 (1), 335, 337, 340 (2), 238, 228, 229, 344 के तहत संबंधित पर कार्रवाई की जा सकती है. जिसमें 10 हजार रुपए से अधिक जुर्माना और 7 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है.

जेडी कार्यालय में नहीं उपलब्ध कराए दस्तावेज

शिकायत के आधार पर जेडी कार्यालय सागर द्वारा सीएमओ दिनेश तिवारी से जन्मतिथि के सत्यापन के लिए हाईस्कूल, हायर सेकंडरी से संबंधित अंकसूची, पेनकार्ड और आधार कार्ड की छायाप्रति मांगी गई. लेकिन तिवारी ने कोई दस्तावेज नहीं भेजे. जिसके बाद ई नगर पालिका पोर्टल संचालन में लगने वाले सीएमओ के दस्तावेजों के आधार पर जांच की गई. पोर्टल में संबंधित अधिकारी-कर्मचारी की जन्मतिथि सहित अन्य विवरण संबंधित निकाय द्वारा अंकित किए जाते हैं. जिसके अनुसार सीएमओ की जन्मतिथि 17 नवंबर 1961 पाई गई.

सनातन विवाद पर भोपाल में धर्म संसद

- 13 अखाड़े होंगे शामिल
- पिछली धर्म संसद में ये हुए थे प्रस्ताव

भोपाल, 11 जुलाई. धर्म, सनातन और शास्त्रों को लेकर देशभर में जारी विवादों के बीच अब साधु-संतों ने बड़ा निर्णय लिया है. राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य सनातन धर्म पर हो रहे कथित हमलों और जातिवादी-राजनीतिक मतभेदों के बीच एक समरस मंच तैयार करना है.

अखिल भारतीय संत समिति मध्यप्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद महाराज ने कहा कि यह सनातन विरोधी ताकतों का षड्यंत्र है जो जाति-वर्ण संघर्ष को भड़का कर धर्म को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, इसी के खिलाफ साधु-संत, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, शंकराचार्य और प्रमुख कथावाचक धर्म संसद में जुटेंगे. देवकीनंदन ठाकुर समेत कई प्रमुख संतों को भी आमंत्रित किया गया है. इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ 2025 में धर्म संसद हुई थी, जिसमें सनातन बोर्ड के गठन, प्राचीन मंदिरों की सुरक्षा, तीर्थों के संरक्षण और सनातन को वैश्विक स्तर पर फैलाने जैसे प्रस्ताव पारित किए गए थे. अब भोपाल की धर्म संसद में इन बिंदुओं पर आगे की रणनीति बनेगी.

विवादों की पृष्ठभूमि में आयोजन: हाल के दिनों में मनुस्मृति दहन (भोपाल), सुंदरकांड की चौपाई पर राजनीति (महाराष्ट्र), कथावाचक पर टिप्पणी (इटावा) जैसे मामले सामने आए हैं. इन्हीं घटनाओं ने धर्म संसद की ज़रूरत को और प्रासंगिक बना दिया है.

राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज

कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार ने इसे बीजेपी-आरएसएस की साजिश बताया और कहा कि संविधान की आड़ में जातिवादी मानसिकता बढ़ रही है. वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को सनातन शब्द से ही नफरत है और वह सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है. भोपाल में होने जा रही यह धर्म संसद न केवल सनातन की रक्षा के लिए मंच बनेगी बल्कि आने वाले समय में धर्म और राजनीति के रिश्तों को भी नई दिशा दे सकती है.

सिंहस्थ में जलमार्ग परिवहन की भी सुविधा देगी सरकार : यादव

उज्जैन. मध्यप्रदेश के उज्जैन में आगामी सिंहस्थ में यात्रियों को धार्मिक स्थलों तक सुगमता से पहुंचाने के लिए राज्य सरकार वायु और सड़क मार्ग के साथ ही जल मार्ग परिवहन की भी सुविधा प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल इस बारे में अपने बयान में कहा कि मां क्षिप्रा की पवित्रता सदा से उज्जैन का आकर्षण रही है.

सड़क मांगने पर मिला तंज

सांसद बोले-पहले से अस्पताल में भर्ती कर देंगे

सीधी, 11 जुलाई. सीधी जिले के एक ग्रामीण इलाके में सड़क की मांग कर रही एक गर्भवती महिला को बीजेपी सांसद से ताना मिला है. बोले-डिलीवरी की तारीख बता दो, पहले ही अस्पताल में भर्ती करा देंगे. सीधी जिले के एक छोटे से गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर एक साल पहले वायरल हुआ वीडियो इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बन गया है. इस वीडियो में गर्भवती महिला लीला साहू गांव तक सड़क की मांग करते हुए अपनी समस्याएं बता रही हैं. लेकिन जवाब में सांसद राजेश मिश्रा का कथित बयान, 'पहले से भर्ती करा देंगे' अब यह आलोचना का केंद्र बन गया है.

गांव तक पहुंचने वाली करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क आज तक नहीं बन पाई है. गांव में 6 महिलाएं गर्भवती हैं और खराब रास्तों के कारण एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती. महिला द्वारा समस्या बताने पर सांसद मिश्रा ने व्यंग्य करते हुए कहा कि सड़क हम नहीं इंजीनियर बनाते हैं. जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की असंवेदनशील प्रतिक्रिया पर स्थानीय लोगों में भारी रोष दिखाई दे रहा है.

मंत्री का भी गैर-जिम्मेदाराना बयान

राज्य के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने भी इस मामले पर विवादास्पद बयान दिया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने से सड़क नहीं बनती. ग्रामीणों का कहना है कि आवेदन कई बार दिए गए, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई. आखिर सोशल मीडिया ही उनकी अंतिम आवाज़ क्यों न बने?

जनता का सवाल-समाधान कब

स्थानीय सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने सरकार से तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है. साथ ही सांसद और मंत्री की टिप्पणियों पर माफी और जवाबदेही तय करने की भी मांग उठ रही है.

सोशल मीडिया बना जनता की आवाज़

आज जब डिजिटल युग में सोशल मीडिया आम नागरिक की बात कहने का मंच बन चुका है, ऐसे में जनप्रतिनिधियों द्वारा उसकी अनदेखी लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी मानी जा रही है. लीला साहू के वीडियो के दोबारा वायरल होने के बाद यह स्पष्ट है कि गांव की स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन सांसद और मंत्री जवाब देने से बचते नज़र आ रहे हैं.

जदयू प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल का 3 दिवसीय भोपाल प्रवास

भोपाल. जनता दल (यू) मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल 3 दिवसीय भोपाल प्रवास पर रहेंगे. वे 12 जुलाई को जबलपुर से सड़क मार्ग द्वारा नागपुर प्रस्थान करेंगे एवं इसके बाद नागपुर से सड़क मार्ग द्वारा भोपाल पहुंचेंगे. इस प्रवास के दौरान सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को अध्यक्ष भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. जहां वे भोपाल के पदाधिकारियों एवं विभिन्न जिलों से आए हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. यह भेंट संगठनात्मक समन्वय, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं संगठन विस्तार के विषय में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

विकास मिश्रा बने सीएम सचिवालय में उप सचिव

आलोक कुमार सिंह को सचिव सीएम का अतिरिक्त प्रभार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 11 जुलाई. मुख्यमंत्री सचिवालय में नई जमावट का सिलसिला लगातार जारी है. यहां नीरज मंडलोई को अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री पदस्थ करने के बाद अब विकास मिश्रा उप सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को अब उप सचिव मुख्यमंत्री पदस्थ किया गया है.

वहीं आलोक कुमार सिंह प्रबंध संचालक मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल को अपने मौजूदा दायित्वों के साथ सचिव मुख्यमंत्री का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा गया है. इस समय मुख्यमंत्री सचिवालय में दो सचिव स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं. इनमें सीबी चक्रवर्ती एम. और इलैया राजा टी. शामिल हैं. अब अतिरिक्त प्रभार के रूप में आलोक कुमार सिंह की भी आमद हो गई है. इससे मुख्यमंत्री सचिवालय में तीन सचिव स्तर के अधिकारी हो जाएंगे.

हम ओवरऐज हो रहे नौकरी कब मिलेगी

- शिक्षक भर्ती की तीसरी काउंसलिंग कराने वेटिंग वाले आंदोलन की राह पर

भोपाल, 11 जुलाई. शिक्षक पात्रता परीक्षा में पात्र एमपी के हजारों कैंडिडेट्स को अब ओवर एज की चिंता सताने लगी हैं. ऐसे में तीसरी काउंसलिंग और प्रदेश की स्कूलों के 8000 पदों पर जल्द भर्ती की मांग तेज होने लगी है.

श्यामलाल रविदास ने बताया कि शिक्षक भर्ती 2018 की पात्रता परीक्षा में हजारों कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे. उनकी तीसरी काउंसलिंग अब तक नहीं हो पाई है. ऐसे में राज्य सरकार द्वारा खाली पदों पर भर्ती भी नहीं की गई. पिछले 7 साल में अधिकांश पात्र कैंडिडेट्स ओवर एज की वजह से अपात्र हो चुके हैं. अब अन्य कैंडिडेट्स को भी ओवर एज का डर सताने लगा हैं. इस परीक्षा में हजारों अभ्यर्थी पास हुए थे. इसकी दो काउंसलिंग हो चुकी हैं.

8000 पदों की भर्ती को लेकर अभ्यर्थी तीसरी काउंसलिंग की मांग कर रहे हैं. अभी शिक्षा विभाग में सभी कैटेगरी के करीब 80,000 पद रिक्त हैं. माध्यमिक शालाओं में 2237 पद शेष रिक्त हैं. इसमें हिंदी, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषय शामिल हैं.

सात साल में हुई दो काउंसलिंग

2018 की पात्रता परीक्षा पास कर चुके कैंडिडेट्स की अब तक दो काउंसलिंग हुई हैं. तीसरी काउंसलिंग के लिए पिछले सात साल से कैंडिडेट्स सरकार से मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हो पाई. तीसरी काउंसलिंग कराने और खाली पदों पर जल्द भर्ती की मांग लेकर कैंडिडेट्स भोपाल लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट पर रोक दिया गया.

बीएमएचआरसी को मिली राष्ट्रीय पहचान

भोपाल, 11 जुलाई. राजधानी के भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) को एक बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल हुई है. देशभर में चुनिंदा संस्थानों को शामिल कर बनाए गए इंडियन बायोडोसिमीट्री नेटवर्क में साबीएमएचआरसी की इटोजेनेटिक प्रयोगशाला को शामिल किया गया है.

- रेडिएशन मात्रा की जांच करेगी यहां की लैब

इसके तहत यह लैब अब रेडिएशन के कारण होने वाली आपदा की स्थिति में रेडिएशन के असर का वैज्ञानिक आकलन करेगी और गंभीर परिस्थितियों में इलाज करने के लिए सटीक जानकारी देगी. इस उपलब्धि के साथ बीएमएचआरसी मध्य भारत का पहला और इकलौता संस्थान बन गया है, जिसे इस अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क में स्थान मिला है. देश में परमाणु ऊर्जा, उद्योग और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रेडिएशन का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. खासतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में रेडियोथेरेपी जैसी तकनीकों के माध्यम से रेडिएशन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है. ऐसे में यदि कभी किसी जगह पर रेडिएशन का रिसाव हो जाए या किसी को अनजाने में ज़्यादा मात्रा में रेडिएशन लग जाए, तो डॉक्टरों को इलाज शुरू करने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि मरीज को कितनी मात्रा में रेडिएशन से प्रभावित हुआ है. बायोडोसिमीट्री वह वैज्ञानिक तरीका है जिससे यह पता लगाया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में रेडिएशन की कितनी मात्रा गई है.

रुपए की समस्या पर आज सेमिनार, हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कैत आएंगे

भोपाल, 11 जुलाई. भोपाल. सिद्धार्थ मैमोरियले फाऊंडेशन द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के रुपए की समस्या, उसकी उत्पत्ति और समाधान शोध के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक सेमिनार का आयोजन शनिवार को होगा.

आयोजन बीएसएसएस इन्स्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कॉलेज दाना पानी रोड बावडिया के सभागार में 12 जुलाई को सुबह 9.30 बजे से होगा, सिद्धार्थ मैमोरियल फाऊंडेशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जाटव ने बताया कि इस राष्ट्रीय सेमिनार के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मप्र उच्च न्यायालय होंगे. प्रो. शक्ति कुमार जेएनयू दिल्ली, जीपी कबीर पंथी वरिष्ठ आईएएस, धर्म पाल क्षेत्रीय प्रबंधक एलआईसी मध्य क्षेत्र मप्र छग, केके एल गौतम अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, दिनेश कसारिया चीफ मैनेजर एसबीआई, डा वीरेन्द्र सिंह मटसेनिया केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर, एम डब्ल्यू अंसारी पूर्व डीजीपी तथा आयोजन को अध्यक्षता डा. जीएस चौहान संयुक्त सचिव भारत सरकार दिल्ली करेंगे.

इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और रुपये का महत्व समझेंगे. समिति के प्रवक्ता सुरेश जाधव ने बताया कि मप्र उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत का अभिनंदन किया जाएगा.

खिलाड़ियों को एक्सचेंज प्रोग्राम

भोपाल, 11 जुलाई. सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने शुक्रवार को मध्यप्रदेश पुरूष हॉकी खेल अकादमी की समीक्षा की. मंत्री सारंग ने अकादमी में प्रशिक्षण, खिलाड़ियों की प्रगति, आधारभूत सुविधाओं एवं अकादमी संचालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

बैठक के दौरान मंत्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश को हॉकी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने 'प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम' प्रारंभ करने की घोषणा की. इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी देश एवं विदेश की प्रतिष्ठित अकादमियों में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि इससे खिलाड़ियों के कौशल में उल्लेखनीय सुधार होगा और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे. मंत्री सारंग ने निर्देश दिए कि अकादमी में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विदेशी विशेषज्ञ कोचों को भी आमंत्रित किया जाए.

राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन आज

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में उज्जैन में राज्य स्तरीय निषादराज सम्मेलन आज आयोजित होगा. यह आयोजन मछुआ समाज को सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों को और भी मजबूती देगा. मछुआ समुदाय की सामाजिक समरसता और आधुनिक मछली पालन की दिशा में यह सम्मेलन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास राज्यमंत्री नारायण सिंह पंवार, उज्जैन के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल की मौजूदगी में मछुआरों को हितलाभ वितरण और अनेक सौगातें दी जाएंगी.

अतिक्रमण पर चला निगम का हथौड़ा

करोंद कृषि उपज मंडी से नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया.

अव्यवस्था | जिला पंचायत की साधारण सभा की बैठक में सदस्यों ने उठाया मुद्दा

गांवों के कई स्कूल भवन जर्जर, हादसा हुआ तो जिम्मेदार कौन?

भोपाल/बैरसिया, 11 जुलाई. भोपाल जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति एवं साधारण सभा की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष रामकुवर नौरंग सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित हुई. सीईओ इला तिवारी ने अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का एजेंडा रखकर कार्रवाई शुरू की.

शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सदस्य विनय मेहर ने ग्रामीण क्षेत्र के 25 वर्षों से अधिक पुराने स्कूल भवनों की दशा के बारे में सदन को बताया कि स्कूल भवन जर्जर हालत में है. बरसात में पानी टपकता है और बच्चे बैठकर

पढ़ाई करते हैं. ऐसे स्कूल भवनों को चिन्हित कर उन्हें तोड़ा जाए और नए भवन बनाए जाएं. नहीं तो कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है. मेहर ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई.

जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहनसिंह जाट ने बैरसिया रोड पर हो रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाते हुए खनन विभाग के अधिकारी अशोक नागले को घेरा. उपाध्यक्ष जाट ने चिल्ला-चिल्ला कर सदन में सबूतों को दिखाते हुए कहा कि खनिज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ग्राम पंचायत ईंटखेड़ी के ग्राम मस्तीपुर, बिनपुर, रतटल खजूरी, पूरा छिंदवाड़ा, कोढी, मनी खेड़ी, करदई एवं ग्राम पंचायत शाहपुर में अवैध उत्खनन हो रहा है. खनन माफिया के द्वारा जितनी परमिशन ली गई है, उससे अधिक जमीन खोद डाली है. हम निरीक्षण करने जाते हैं तो माफिया तक पहले ही सूचना पहुंच जाती है. वह अपनी जेसीबी, पोकलेन मशीन, डंपर वहां से हटा लेते हैं. सागौन के हजारों पेड़ काट डाले हैं. खदानों में तार फेंसिंग नहीं है. पानी भरने के कारण दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है. गिट्टी खदानों एवं खदानों पर तार फेंसिंग की व्यवस्था के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की जाए. बैरसिया विधायक प्रतिनिधि दीपक गुर्जर ने ग्रामीण क्षेत्र में खराब सड़कों की मरम्मत करने की बात कही. इसका सभी सदस्यों ने समर्थन करते हुए पीडब्ल्यूडी एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अधिकारियों को घेरा.

सदस्य मेहर ने बैरसिया क्षेत्र के तेंदूपत्ता संग्रहण करने वाले मजदूरों का रुका पैसा दिलाने की मांग उठाते हुए कहा कि गरीब लोग दिन भर मेहनत करते हुए तेंदूपत्ता तोड़ते हैं, वन विभाग के अधिकारियों ने उनका पैसा रोक लिया है. बैठक में अन्य सदस्यों ने भी समस्याओं को प्रमुखता से रखा. सीईओ तिवारी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सदस्यों के द्वारा बताई जा रही समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी कर मुझे सूचित करें. बैठक में मुख्य रूप से रश्मि अवनीश भार्गव, देव कुंवर अनिल हाडा, विक्रम बालेश्वर, गंगा मिश्रीलाल मालवीय, फंदा जनपद अध्यक्ष प्रमोद राजपूत, सदस्य प्रतिनिधि विनोद राजोरिया एवं शिक्षा विभाग, कृषि, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास, उद्यानिकी, सामाजिक न्याय, सहकारिता, वन विभाग आदि के विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

नियमित पदों पर बाहरी भर्ती पर पूरी तरह से लगे रोक

भोपाल. राज्य शासकीय कर्मचारी अधिकार संरक्षण संघ ने राज्य सरकार पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के आर्थिक शोषण एवं जीवन बर्बाद करने का आरोप लगाया है. संघ के अध्यक्ष शील प्रताप सिंह पुंडीर ने सीएम डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपा है. बताया कि जहां एक ओर निर्माण सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें कभी स्थाई कर्मी तो कभी विनियमितकर्मी वेतन का सुनझुना थमाया जाता है. जिससे उनका जीवन बर्बाद हो रहा है. नियमित पदों पर बाहरी भर्ती द्वारा कई पदों को भरा जा रहा है. यह कार्यरत अन्य कर्मियों के साथ कुठाराघात है. वहीं संगठन के प्रांतीय सचिव कृष्णकांत मिश्रा ने बताया कि दैनिक वेतन भोगियों को प्राथमिकता देते हुए 10, 20 और 25 वर्षों से नियमित होने की आशा में उम्र दराज हो गए और कुछ सेवानिवृत्ति की कगार पर पहुंच हैं, सरकार उनकी उम्मीदों पर पानी फेरती हुई दिखाई दे रही है. उनका कहना है कि इन कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, जो बर्दास्त करने लायक नहीं है. इस विसंगति से कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता है. उन्होंने बताया कि हमारी मांग है कि सरकारी शोषण के शिकार दैनिक वेतन भोगी संवर्ग की सेवाएं तत्काल नियमित की जाएं, इससे सरकार के प्रति कर्मचारियों में सकारात्मकता आएगी.